2025: CGHC: 42807

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1356/2023

गोपाल प्रसाद नायक पिता गिरधारी लाल नायक,

उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जांजगीर,

जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव

तकनीकी शिक्षा विभाग,

मंत्रालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर,

रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग,

मंत्रालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर,

रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----उत्तरवादी

(वाद – शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है।)

याचिकाकर्ता की ओर से: सुश्री दीक्षा गौराहा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री अंकुर कश्यप, उप–शासकीय अधिवक्ता

2025: CGHC: 42807

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

दिनांक 22.08.2025

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष के साथ दायर की गई है:

> "10.1 कि, माननीय न्यायालय दिनांक 21.12.2022 का आक्षेपित आदेश (P/1) जो निदेशक, तकनीकी शिक्षा, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है, को रद्द करने की महान कृपा करें ;
>
> 10.2 कि, माननीय न्यायालय निदेशक, तकनीकी शिक्षा, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा याचिकाकर्ता को भेजा गया आक्षेपित पत्र दिनांक 30/01/2023 (P/2) को रद्द करने की महान कृपा करें ;
>
> 10.3 कि, माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी भी अन्य अनुतोष को वह उचित और सही समझे, प्रदान करने की महान कृपा करें ;"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को शुरुआत में 1996 में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जांजगीर–चांपा में प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया, जहाँ वह ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। निदेशक, तकनीकी शिक्षा, नया रायपुर ने दिनांक 21.12.2022 के आदेश के माध्यम से, आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें वर्ष 2006 से याचिकाकर्ता को किए गए कथित अधिक भुगतान की वसूली और वेतन निर्धारण में संशोधन का निर्देश दिया गया। दिनांक 28.02.2013 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता का वेतन सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुसार वृत्ति उन्नयन स्कीम के तहत संशोधित किया गया था, और इसी तरह, दिनांक 23.02.2017 के आदेश के माध्यम से,

याचिकाकर्ता को विभागाध्यक्ष (कैमिकल इंजीनियरिंग) के पद पर पदोन्नत किया गया और वेतन निर्धारण संशोधित किया गया। ये दोनों आदेश उत्तरवादी प्राधिकरणों द्वारा स्वयं पारित किए गए थे, जिसमें अधिक भुगतान या वसूली की देयता का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार के निर्धारण के आधार पर, उन्होंने पर्याप्त शिक्षा और आवास ऋण भी लिया है, और इस स्तर पर वसूली से उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाई और अपूरणीय क्षति होगी। निदेशक, तकनीकी शिक्षा को दिनांक 22.12.2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वसूली पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। निर्धारण में कोई भी त्रुटि पूरी तरह से उत्तरवादियों के कारण है, और 16 साल बाद वसूली मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और विधि में अस्थिर है। कोई अन्य प्रभावी उपाय न होने के कारण, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष न्याय की मांग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को शुरुआत में वर्ष 1996 में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जांजगीर–चांपा में प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया, जहाँ वह अत्यंत ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। याचिकाकर्ता को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब निदेशक, तकनीकी शिक्षा, नया रायपुर ने दिनांक 21.12.2022 का आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें वर्ष 2006 से किए गए कथित अधिक भुगतान की वसूली और वेतन निर्धारण में संशोधन का निर्देश दिया गया। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की अपनी वेतन निर्धारण में कोई भूमिका नहीं थी। निर्धारण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार किया गया था। दिनांक 28.02.2013 के आदेश के माध्यम से, कमेटी की सिफारिश पर वृत्ति उन्नयन स्कीम के तहत याचिकाकर्ता के वेतनमान को संशोधित किया गया था, और इसी तरह, दिनांक 23.02.2017 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता को विभागाध्यक्ष (कैमिकल इंजीनियरिंग) के पद पर पदोन्नत किया गया और वेतन निर्धारण संशोधित किया गया। ये दोनों आदेश उत्तरवादी प्राधिकरणों द्वारा स्वयं पारित किए गए थे, और किसी भी समय यह उल्लेख नहीं किया गया था कि निर्धारण अनंतिम था या किसी भी अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने ₹74,00,000/– का गृह ऋण और ₹7,50,000/– का शिक्षा ऋण लिया है और वह पहले से ही ₹89,373/– की मासिक क़िस्त का भुगतान कर रहा है। यदि 16 साल बाद

अब वसूली की जाती है, तो इससे याचिकाकर्ता को गंभीर वित्तीय कठिनाई और अपूरणीय क्षति होगी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि निर्धारण में कोई भी त्रुटि , यदि कोई है, तो उसके लिए केवल उत्तरवादी प्राधिकरण जिम्मेदार हैं, न कि याचिकाकर्ता। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह, [(2015) एआईआर एससीडब्ल्यू 501] के फैसले का अवलंब लिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ श्रेणियों में अधिक भुगतान की वसूली अस्वीकार्य है, जिसमें वह स्थिति शामिल है जब अधिक भुगतान पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया गया हो, और जहाँ ऐसी वसूली कठोर, मनमानी और अनुचित होगी। याचिकाकर्ता का मामला उक्त निर्णय के खंड (iii) और खंड (v) के अंतर्गत आता है।

5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने बारे लाल उइके बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, रिट याचिका क्रमांक 6009/2018 में, रफीक मसीह (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि का पालन करते हुए, इसी तरह के वसूली आदेशों को रद्द कर दिया है, यह मानते हुए कि जब कर्मचारी गलत निर्धारण या अधिक भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो वसूली नहीं की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पूरी तरह से मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और विधि में अस्थिर है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता पर बिना किसी गलती के 16 साल की अवधि की वसूली का बोझ डालता है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि दिनांक 21.12.2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाए, और उत्तरवादियों को याचिकाकर्ता से कोई भी वसूली करने से रोका जाए।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य [2022 एससीसी ऑनलाईन एससी 536] और जोगेश्वर साहू और अन्य बनाम जिला न्यायाधीश, कटक और अन्य [2025 एससीसी ऑनलाईन एससी 724] के फैसलों का अवलंब लिया है, जिसमें यह माना गया है कि जब नियोक्ता द्वारा नियमों की गलत व्याख्या के कारण, और कर्मचारी द्वारा किसी धोखाधड़ी, गलत बयानी, या तथ्यों को छिपाने के कारण नहीं, किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान किया जाता है, तो ऐसे अधिक भुगतान की वसूली अस्वीकार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की है कि ऐसी कोई भी वसूली, विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के बाद और सुनवाई का अवसर दिए बिना, अनुचित, मनमानी और विधि में अस्थिर होगी।

8. इस न्यायालय के शंकर नारायण चक्रवर्ती बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, रिट याचिका क्रमांक 9716/2019, दिनांक 30.01.2020 को निस्तारित, और एन.एन. द्विवेदी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, रिट याचिका क्रमांक 6218/2023 और समान मामले, दिनांक 26.11.2024 को निस्तारित, के फैसलों पर भी आगे भरोसा किया गया है। पूर्वोक्त मामलों में, इस न्यायालय ने माना है कि किसी भी वैधानिक नियम के अभाव में, कर्मचारी द्वारा दिया गया कोई अंडरटेकिंग (वचनपत्र) कथित अधिक भुगतानों की वसूली को सही ठहराने के लिए बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है।

9. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 21.12.2022 का आक्षेपित आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेख की उचित जांच के बाद सही ढंग से पारित किया गया है। यह ज़ोर दिया गया है कि याचिकाकर्ता गलत वेतन निर्धारण के कारण अपनी पात्रता से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, जिसका पता बाद में ऑडिट और सत्यापन के दौरान चला। एक बार जब ऐसी अनियमितता अधिकारियों के संज्ञान में आई, तो सार्वजनिक कोष को अनुचित नुकसान से बचाने के लिए वेतन निर्धारण को ठीक करना और अधिक राशि की वसूली करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि "किसी को भी राज्य की कीमत पर अनुचित रूप से समृद्ध नहीं होना चाहिए" का सिद्धांत वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होता है। याचिकाकर्ता ने 16 साल से अधिक समय तक वित्तीय लाभों का आनंद लिया है, और इसलिए अब वह यह तर्क देकर मुकर नहीं सकता कि राज्य को अधिक भुगतान की वसूली करने से रोका जाए। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि निर्धारण के समय अंडरटेकिंग (वचनपत्र) देना और उसके तहत लाभों को स्वीकार करना याचिकाकर्ता को अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी बाद के सुधार का पालन करने के लिए बाध्य करता है। वह यह भी तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन फैसलों का अवलंब लिया है, वे तथ्यों के आधार पर अलग हैं क्योंकि उन मामलों में वसूली या तो सेवानिवृत्ति के बाद या सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना मांगी गई थी, जबकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता अभी भी सेवा में है और उसे अभ्यावेदन के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अनुचित संवर्धन का सिद्धांत, साथ ही सरकारी निधियों की सुरक्षा की सरकार की बाध्यता, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई कठिनाई की दलील से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तदनुसार, आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों को सुना और रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

11.हाल ही में, जोगेश्वर साहू (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> "8. इस संबंध में विधि को इस न्यायालय ने समय–समय पर दिए गए कई फैसलों में तय कर दिया है; जैसे: साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) Supp (1) SCC 18, श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ, (1994) 2 SCC 521, भारत संघ बनाम एम. भास्कर, (1996) 4 SCC 416 और वी. गंगाराम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, (1997) 6 SCC 139 और थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) SCC ऑनलाईन SC 536 के हालिया निर्णय में।
>
> 9. इस न्यायालय ने लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यदि अधिक राशि का भुगतान कर्मचारी की ओर से किसी मिथ्या–व्यपदेशन या धोखाधड़ी के कारण नहीं किया गया था, या यदि ऐसा अधिक भुगतान नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करने पर, या नियम/आदेश की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर किया गया था, जो बाद में गलत पाया जाता है, तो परिलब्धियों या भत्तों के ऐसे अधिक भुगतान वसूली योग्य नहीं हैं। यह माना गया है कि वसूली के खिलाफ ऐसी राहत कर्मचारी के किसी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि न्यायसंगतता (equity) में है, जो न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए कर्मचारी को उस कठिनाई से राहत प्रदान करने के लिए है, जो वसूली का आदेश दिए जाने पर होगी।
>
> 10.थॉमस डेनियल (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने पैरा 10, 11,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12 और 13 में इस प्रकार माना है:

"10. साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य में, इस न्यायालय ने उस भुगतान की वसूली को रोक दिया था जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक आदेश की गलत व्याख्या के कारण, कर्मचारी की ओर से किसी मिथ्या–व्यपदेशन के बिना, उन्नत वेतनमान के तहत दिया गया था। यह इस प्रकार माना गया था:

> "5. निःसंदेह अपीलकर्ता के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता छूट का हकदार नहीं होगा। प्राचार्य ने उसे छूट देने में गलती की। छूट की तारीख से, अपीलकर्ता को संशोधित वेतनमान पर उसका वेतन दिया गया था। हालांकि, यह अपीलकर्ता द्वारा की गई किसी मिथ्या–व्यपदेशन के कारण नहीं है कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, बल्कि प्राचार्य द्वारा की गई गलत व्याख्या के कारण है जिसके लिए अपीलकर्ता को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, आज तक भुगतान की गई राशि को अपीलकर्ता से वसूला नहीं जा सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमानों पर लागू नहीं होगा। अपील आंशिक रूप से बिना किसी लागत के स्वीकार की जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.कर्नल बी.जे. अक्करा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार में, इस न्यायालय ने एक समान प्रश्न पर विचार किया, जैसा कि निम्नलिखित है:

"27. विचार किया जाने वाला अंतिम प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 7–6–1999 के सर्कुलर की गलत व्याख्या/समझ के कारण किए गए अधिक भुगतान की वसूली के खिलाफ राहत दी जानी चाहिए। इस न्यायालय ने लगातार एक कर्मचारी से परिलब्धियों/भत्तों के अधिक गलत भुगतान की वसूली के खिलाफ राहत दी है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं (देखें साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य [1995 Supp (1) SCC 18 : 1995 SCC (L&S) 248], श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ [(1994) 2 SCC 521 : 1994 SCC (L&S) 683 : (1994) 27 एटीसी 121], भारत संघ बनाम एम. भास्कर [(1996) 4 SCC 416 : 1996 SCC (L&S) 967] और वी. गंगाराम बनाम क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक [(1997) 6 SCC 139 : 1997 SCC (L&S) 1652]):

(क) अधिक भुगतान कर्मचारी की ओर से किसी मिथ्या–व्यपदेशन या धोखाधड़ी के कारण नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) ऐसा अधिक भुगतान नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करने पर, या नियम/आदेश की किसी विशेष व्याख्या के आधार पर किया गया था, जो बाद में गलत पाया जाता है।

28.अधिक बैक पेमेंट की वसूली को रोकने वाली ऐसी राहत, न्यायालयों द्वारा कर्मचारी में किसी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि न्यायसंगतता में, न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को उस कठिनाई से राहत देने के लिए दी जाती है जो वसूली लागू होने पर होगी। एक सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से सेवा के निचले स्तर का, अपनी परिलब्धियों को अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए खर्च करेगा। यदि उसे लंबे समय तक अधिक भुगतान प्राप्त होता है, तो वह इसे खर्च कर देगा, वास्तव में यह मानते हुए कि वह इसका हकदार है। चूंकि अधिक भुगतान को वसूलने की कोई भी बाद की कार्रवाई उसे अनावश्यक कठिनाई देगी, इसलिए इस संबंध में राहत दी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाती है। लेकिन जहां कर्मचारी को पता था कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत तरीके से भुगतान किया गया था, या जहां गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर त्रुटि का पता चल जाता है या उसे ठीक कर दिया जाता है, तो न्यायालय वसूली के खिलाफ राहत नहीं देंगे। यह मामला न्यायिक विवेक के दायरे में होने के कारण, न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वसूली के खिलाफ ऐसी राहत देने से मना कर सकते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"29. इसी सिद्धांत पर, पेंशनभोगी भी यह निर्देश मांग सकते हैं कि गलत भुगतान की वसूली नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सेवारत कर्मचारियों की तुलना में पेंशनभोगी अधिक नुकसानदेह स्थिति में होते हैं। अधिक गलत भुगतान को वसूलने का कोई भी प्रयास उन्हें अनावश्यक कठिनाई देगा। याचिकाकर्ता अधिक भुगतान के संबंध में किसी भी मिथ्या–व्यपदेशन या धोखाधड़ी के दोषी नहीं हैं। एनपीए को न्यूनतम वेतन में जोड़ा गया था, स्टेपिंग अप के प्रयोजनों के लिए, जो कार्यान्वयन विभागों की गलत समझ के कारण हुआ था। इसलिए, हमारा विचार है कि उत्तरवादी दिनांक 7–6–1999 के सर्कुलर के अनुसरण में किए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली नहीं करेंगे, जब तक कि दिनांक 11–9–2001 का स्पष्टीकरण सर्कुलर जारी नहीं हो जाता। जहाँ तक 11–9–2001 के सर्कुलर के बाद किए गए किसी भी अधिक

भुगतान का संबंध है, जाहिर है, भारत संघ अधिक राशि वसूलने का हकदार होगा क्योंकि उक्त सर्कुलर की वैधता को बरकरार रखा गया है और पेंशनभोगियों को पहले की गई गलत गणनाओं के संबंध में नोटिस दिया गया है।"

12.सैयद अब्दुल कादिर बनाम बिहार राज्य के मामले में, अधिक भुगतान की वसूली की मांग की गई थी जो प्रचलित बिहार राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, 1983 की गलती और गलत व्याख्या के कारण अपीलकर्ता–शिक्षकों को किया गया था। वहाँ अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि भले ही यह माना जाए कि अपीलकर्ता पदोन्नति पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं थे, लेकिन अधिक राशि उनसे वसूली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी ओर से किसी मिथ्या–व्यपदेशन या धोखाधड़ी के बिना भुगतान की गई थी। न्यायालय ने माना कि ऐसी स्थिति में अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और अधिक भुगतान की वसूली का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब कर्मचारी बाद में सेवानिवृत्त हो चुका हो। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सामान्य बोलचाल में, न्यायालय वसूली को वहाँ प्रतिबंधित करते हैं जहाँ कर्मचारी की ओर से कोई मिथ्या–व्यपदेशन या धोखाधड़ी नहीं होती है और जब अधिक भुगतान किसी नियम या आदेश की गलत व्याख्या/समझ को लागू करके किया गया हो। यह इस प्रकार माना गया था:

"59. निस्संदेह, अपीलकर्ता शिक्षकों को भुगतान की गई अधिक राशि उनकी ओर से किसी मिथ्या–व्यपदेशन या धोखाधड़ी के कारण नहीं थी और अपीलकर्ताओं को भी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें जो राशि दी जा रही थी वह उनकी हकदारी से अधिक थी। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि वित्त विभाग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया था कि यह उनकी ओर से एक सद्भावपूर्ण गलती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया अधिक भुगतान उन पर लागू होने वाले नियम की गलत व्याख्या का परिणाम था, जिसके लिए अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि, पूरा भ्रम बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता, लापरवाही और असावधानी के कारण था। अपीलकर्ता शिक्षकों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश लाभार्थी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपीलकर्ता शिक्षकों को किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता शिक्षकों को अधिक भुगतान की गई राशि की कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. रफीक मसीह (वाइट वॉशर) में, इस न्यायालय ने लाभार्थी कर्मचारियों को उनकी बिना किसी गलती या प्राप्तकर्ता के इशारे पर मिथ्या–व्यपदेशन के कारण उनकी पात्रता से अधिक गलत तरीके से बढ़ाए गए मौद्रिक लाभों को वसूलने के लिए राज्य द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच की। इस न्यायालय ने एक कर्मचारी को होने वाली कठिनाई की स्थितियों पर विचार किया, यदि नियोक्ता को प्रतिपूर्ति के लिए वसूली का निर्देश दिया जाता है, और उसी को अस्वीकार कर दिया, लाभार्थी कर्मचारियों को ऐसी वसूली से छूट दी। यह इस प्रकार माना गया था:

"8. दो पक्षों के बीच, यदि एक निर्धारण उस पक्ष के पक्ष में दिया जाता है, जो दोनों में कमजोर है, दूसरे (जो वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य है) को कोई गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना, तो हल किया गया मुद्दा न्याय की अवधारणा के अनुरूप होगा, जो भारत के नागरिकों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी सुनिश्चित किया गया है। नियोक्ता द्वारा वसूली के अधिकार का पीछा किया जा रहा है, इसकी तुलना संबंधित

कर्मचारी पर वसूली के प्रभाव से करनी होगी। यदि संबंधित कर्मचारी से वसूली का प्रभाव, नियोक्ता के राशि वसूलने के संबंधित अधिकार की तुलना में अधिक अनुचित, अधिक गलत, अधिक अनुचित, और अधिक अवांछित होगा, तो वसूली करना अन्यायपूर्ण और मनमाना होगा। ऐसी स्थिति में, कर्मचारी का अधिकार, नियोक्ता के वसूली के अधिकार को पछाड़ देगा, और इसलिए उसे ढक लेगा।

xxxxxxxxxx

"18. यह संभव नहीं है कि कठिनाई की उन सभी स्थितियों की कल्पना की जाए जो कर्मचारियों पर वसूली के मुद्दे पर शासन करेंगी, जहाँ नियोक्ता द्वारा गलती से, उनकी पात्रता से अधिक भुगतान किया गया हो। जैसा भी हो, यहाँ ऊपर संदर्भित निर्णयों के आधार पर, हम एक त्वरित संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली विधि में अस्वीकार्य होगी:

(i) कक्षा III और कक्षा IV सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) उन कर्मचारियों से वसूली, जहाँ वसूली का आदेश जारी होने से पहले पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिक भुगतान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) उन मामलों में वसूली, जहाँ किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता हुई है, और तदनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे सही मायने में एक निम्न पद पर काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए थी।

(v) किसी भी अन्य मामले में, जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो यह इतनी हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगा, कि यह वसूली करने के नियोक्ता के न्यायसंगत संतुलन के अधिकार से कहीं अधिक होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. विचाराधीन मामले में, अपीलकर्ता स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत थे जब उन्हें विषयगत अवैध भुगतान किया गया था। अभिलेख में यह परिलक्षित नहीं होता है कि ऐसा भुगतान उन्हें किसी धोखाधड़ी या मिथ्या–व्यपदेशन के कारण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जिला न्यायाधीश, कटक द्वारा अपीलकर्ताओं को वित्तीय लाभ बढ़ाया गया, तो बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वसूली का बाद का आदेश आया। यह भी विवादित नहीं है कि भुगतान वर्ष 2017 में किया गया था जबकि वसूली का निर्देश वर्ष 2023 में दिया गया था। हालांकि, इस बीच, अपीलकर्ता वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि वसूली का आदेश जारी करने से पहले अपीलकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। अपीलकर्ता स्टेनोग्राफर के एक मंत्रिस्तरीय पद पर अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं और यह स्वीकार किया जाता है कि

वे किसी राजपत्रित पद पर नहीं थे, इस प्रकार उपर्युक्त उद्धृत निर्णय में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को लागू करते हुए, वसूली अस्थिर पाई जाती है।"

12.मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि वर्तमान मामले में शामिल विवाद अब निर्णय के लिए आवश्यक नहीं रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रफीक मसीह (पूर्वोक्त) में स्पष्ट रूप से माना है कि कथित अधिक भुगतान की वसूली उन मामलों में नहीं की जा सकती जहाँ ऐसा भुगतान कर्मचारी की ओर से किसी गलत बयानी, धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने के कारण नहीं हुआ था, बल्कि वेतन निर्धारण करते समय नियोक्ता द्वारा की गई त्रुटि के कारण हुआ था। इस सिद्धांत को थॉमस डेनियल (पूर्वोक्त) और जोगेश्वर साहू (पूर्वोक्त) में दोहराया गया है, जहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि लंबे समय बीत जाने के बाद वसूली, खासकर जब कर्मचारी ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वेतन के आधार पर अपने वित्तीय मामलों की व्यवस्था कर ली हो, तो यह अन्यायपूर्ण, मनमाना और विधि में अस्थिर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को 1996 में नियुक्त किया गया था, बाद में प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया गया, और उसका वेतन निर्धारण समय–समय पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वयं स्पष्ट आदेशों के माध्यम से किया गया था। किसी भी स्तर पर उसे यह संकेत नहीं दिया गया था कि ऐसा निर्धारण गलत था या वह किसी कथित अधिक भुगतान को वापस करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। सोलह वर्षों से अधिक समय तक, याचिकाकर्ता ऐसे निर्धारण के अनुसार वेतन आहरित करता रहा है। अभिलेख में दूर–दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को गुमराह करने में कोई भूमिका निभाई थी, या वह धोखाधड़ी, गलत बयानी, या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का दोषी था। इन परिस्थितियों में, इस विलंबित चरण में याचिकाकर्ता पर दायित्व डालना पूरी तरह से अनुचित होगा और पूर्वोक्त बाध्यकारी न्यायदृष्टांतों में मान्यता प्राप्त निष्पक्षता, न्यायसंगतता और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

14.इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्देशित वसूली न केवल निर्धारित कानूनी स्थिति की अनदेखी करती है, बल्कि असंतुलित कठिनाई भी पैदा करती है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता

ने पहले ही आवास और शिक्षा ऋण ले रखे हैं और भारी वित्तीय दायित्व के दबाव में है। सोलह वर्षों के बाद कथित अधिक भुगतानों की वसूली का आदेश देने से गंभीर पूर्वाग्रह और अपूरणीय वित्तीय नुकसान होगा, जिसकी अनुमति विधि कर्मचारी की ओर से किसी गलती के अभाव में नहीं देता है।

15.पूर्वोक्त कारणों से, यह न्यायालय इस दृढ़ राय का है कि निदेशक, तकनीकी शिक्षा, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित दिनांक 21.12.2022 का आक्षेपित आदेश, संलग्नक P/1 के तहत, कथित अधिक भुगतान की वसूली का निर्देश देते हुए, विधि में स्थिर नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना उचित है।

16.तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 21.12.2022 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। उत्तरवादियों को कथित अधिक भुगतान के कारण याचिकाकर्ता से कोई भी वसूली करने से रोका जाता है। तथापि, उत्तरवादी याचिकाकर्ता के वेतन निर्धारण को भविष्य में संशोधित/सुधारने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो विधि के अनुसार और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ही किया जाएगा।

17.यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आक्षेपित आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता से कोई वसूली पहले ही की जा चुकी है, तो वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर उसे वापस कर दी जाएगी। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

शीर्ष नोट

कर्मचारी से अधिक भुगतान की वसूली — अस्वीकार्य है यदि जहाँ अधिक भुगतान कर्मचारी की मिथ्या व्यपदेशन, धोखाधड़ी या गलती के कारण नहीं बल्कि नियोक्ता की गलती के कारण हुआ हो। कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा की गई गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur